सिलवासा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसो. ने प्रशासक प्रफुल पटेल को पत्र लिख 31 दिसंबर तक रिफंड...

हाल ही में वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों को डिस्ट्रीब्यूशन / रिफंड करने वाले ऐसे फायदों को मौजूदा यूनिटों को दिया है जो अवशिष्ट के लिए इस तरह के लाभ के पात्र हैं। इसी प्रकार दादरा एवं नगर हवेली में कई ऐसी ईकाईयां भी हैं, जो 31-12-2017 तक केन्द्रीय बिक्री कर के इस लाभ की हकदार हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उद्योगों को मजबूती देने के लिए इस पिछड़े क्षेत्र की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और यहां के उद्योगों को रिफंड देने की जरूरत है जो 31-12-2017 तक लाभ के हकदार हैं। गौरतलब है कि इस छोटे से क्षेत्र में 2500 से अधिक औद्योगिक ईकाईयां हैं और ये ईकाईयां सरकारी खजाने को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से योगदान दे रही हैं, जो देश के सभी महत्वपूर्ण उत्पादनों को पूरा करती हैं और विदेश (प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई) और औद्योगिक बाधाओं / गड़बड़ी आदि के बिना कर्मचारियों / उद्यमियों के सभी स्तरों पर ईमानदारी और दृढ़ता से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में मदद कर रही है। सिलवासा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसो. के अध्यक्ष चंद्रकांत पारेख ने प्रशासक प्रफुल पटेल, दानह सांसद नटू पटेल को पत्र लिख इस मामले में संघ प्रदेश के हित में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इसी सिलसिले में वित्त मंत्री अरूण जेटली को भी पत्र लिखा है।

संघ प्रदेश दमण एवं दीव,
आपदा प्रबंधन सेल, समाहर्तालय, ढोलर, मोटी दमण

No.1/34/COL/CYCLONE/FCR-LIST/2017/7668 Dated: 30/08/2017

परामर्शी

असली आज़ादी Thu, 31 August 2017
www.readwhere.com/read//c/21749717